lisation of minor oilseeds and cotton seed for increasing total oil supply and augmenting domestic supply by arranging import of oilseeds and oils to the extent feasible

Film 'Mohammad Bin Tughlak'

135 SHRI R R SINGH DEO : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state

(a) whether a film entitled 'Mohammad Bin Tughlak' was recently produced in Tamil Nadu by Shri Ramiswamy "Cho" ,

(b) whether the film was approved by Government after extensive cuts , and

(c) if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) (a) to (c) Yes Sir The film 'Mohammad Bin Tughlak" was granted a 'U' certificate subject to twenty cuts on February 27, 1971 The cuts total approximately 83 meters while the total length of the film is about 4000 meters The cuts were imposed in accordance with the Cinematograph Act

Implementation of Recommendation of Second Central Wage Board for Sugar Industry

136 SHRI D K PANDA . Will the Minister of LABOUR AND RLHABILITATION be pleased to state

(a) whether the recommendations of the Second Central Wage Board for Sugar Industry have been implemented ,

(b) if not, the reasons therefor ,

(c) whether Government will lay on the Table the list of sugar mills where the said recommendations have not been implemented , and

(d) what steps have been taken for implementation of the same in the Aska Co-operative Sugar Industries, Aska in the State of Orissa ?

THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI R K KHADILKAR) : (a) to (d). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the table of the house after it is received.

Implementation of Recommendations of Central Electricity Wage Board in Orissa

137 SHRI D. K PANDA : Will the Minister of LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the recommendations of the Central Electricity Wage Board have been implemented by the Orissa State Electricity Board ,

(b) if so, whether the Wage scales have been refixed , and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI R K KHADILKAR) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House after it is received

उर्वरकों की वितरण प्रणाली में सुधार करना

138 डा० लक्ष्मी नारायण पान्डे क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उर्वरकों पर सरकारी नियत्रण तथा त्रुटिपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण किसान उनका समय पर तथा उचित ढग से प्रयोग नही कर पाते है, और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध मे प्रक्रिया मे सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे) (क) जी नहीं ।

वस्तुतः नवम्बर, 1969 से उर्वरकों के व्यापारियों को लाइसेंस देने के स्थान पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था प्रारम्भ कर उर्वरकों का वितरण उदार कर दिया गया है।

(ख) उर्वरकों का वितरण मुख्यत राज्य सरकारों का कार्य है। फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ छमाही क्षेत्रीय बैठकों की प्रणाली द्वारा उर्वरकों की आवश्यकता के तथा राज्य सरकारों को देशीय उत्पादन और आयातों से उर्वरकों की आपूर्ति के मूल्यांकन का समन्वय करती है। जहां तक आयातित उर्वरकों का सम्बन्ध है। इनका वितरण राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों के आधार पर केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में इन उर्वरकों का आगे वितरण अपनी सहकारी समितियों तथा अन्य एजेन्सियों/निजी भागीदारी के माध्यम से करती है। गत वर्ष से, केन्द्रीय उर्वरक पूल सहकारी समितियों, कृषि उद्योग निगमों, जिला परिषदों और गैर-सरकारी लाइसेंस धारियों/रजीकृत वितरकों को उर्वरकों का सीधा भी आबंटन कर रहा है।

राजस्थान में लघु सिंचाई कार्य

श्री मूलचन्द डागा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में दुर्भिक्ष के दौरान, सड़कों, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा भूमि संरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रारंभ किए गये कार्यों को पूरा करने के लिये धन देने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) यदि इन कार्यों को पूरा न किया गया तो क्या इन पर व्यय किये गये करोड़ों रुपये व्यर्थ नहीं चले जाएंगे और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या अपूर्ण सड़कों के कारण संचार साधन अनुपयोगी हो गये हैं जिससे जनता को अत्यधिक असुविधा होती है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) (क) से (घ) राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गयी है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Payment of Project Allowance to P & T Employees at Ranchi

140 SHRI P K GHOSH
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state.

(a) whether Project Allowance to all the Post and Telegraph Staff stationed in Ranchi City has been sanctioned and the same was communicated by the Director General of Posts and Telegraphs, New Delhi to the local authorities in September, 1969

(b) if so, whether all the P and T employees stationed in Ranchi City have been paid the said allowance as per orders, and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Project allowance to the employees of the P and T Department in Ranchi was sanctioned in 1969. The project allowance is normally sanctioned to staff performing duties required in connection with the project and also to staff employed in project areas which are lacking in essential amenities. As Ranchi is a classified city for the purpose of grant of H. R. A. to the